P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-10* June- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

राजस्थान में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन (बून्दी जिले का एक अध्ययन)

Micro Level Planning in Rajasthan (A Study of Bundi District)

Paper Submission: 15/06/2020, Date of Acceptance: 25/062020, Date of Publication: 30/06/2020

संदीप यादव
सह आचार्य,
भूगोल विभाग,
राजकीय महाविधालय,
बून्दी, राजस्थान, भारत

भूपेश जेतवाल
शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
राजकीय महाविधालय,
बून्दी, राजस्थान, भारत

सारांश

ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है कि वहां उपलब्ध सभी प्राकृतिक संसाधनों का सन्तुलित व समुचित उपयोग हो सके। इसके लिए स्थानिक कार्यात्मक नियोजन आवश्यक है। स्थानिक कार्यात्मक नियोजन का अर्थ होता है कि विभिन्न आर्थिक व सामाजिक सुविधाओं का विभिन्न क्षेत्रों में उचित वितरण हो ताकि सर्वांगीण विकास हो सके। वस्तुतः स्थानिक कार्यात्मक नियोजन का अभिप्राय विकास योजनाओं द्वारा विकास की विषमताओं को कुछ सीमा तक दूर करने का प्रयास है। स्थानिक कार्यात्मक नियोजन किसी चयनित क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए वहां उपलब्ध साधनों के आधार पर तैयार की गई योजना है।

प्रस्तुत शोधपत्र में बून्दी जिले के सेवा केन्द्रों का अभिज्ञान सेवाओं की समुपस्थिति एवं अन्योन्याश्रितता के आधार पर किया गया है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में सेवाओं की मात्रा (संख्या) को ध्यान में नहीं रखकर इस बात का ध्यान रखा गया है कि क्षेत्र में सेवा युक्त अधिवासों की संख्या कितनी है ?

For rural development it is necessary that all the available natural resources can be balanced and properly utilized. This requires spatial functional planning. Spatial functional planning means that there is proper distribution of various economic and social facilities in different areas so that all round development can take place. In fact, spatial functional planning refers to an attempt by the development schemes to remove developmental disparities to some extent. Spatial functional planning is a plan prepared for the social, economic and cultural development of a selected region based on the means available there.

In the paper presented, the service centers of Bundi district have been identified on the basis of the overall location and interdependence of the services. In this context, it is noteworthy that the number (in number) of services in the area is not taken into consideration, considering the number of domiciled people in the area?

मुख्य शब्द : प्रादेशिक नियोजन, केन्द्रीय कार्य, केन्द्रीय स्थल, कार्यिक भार, पदानुक्रम।

Regional Planning, Central Work, Central Site, Work Load, Hierarchy.

प्रस्तावना

वर्तमान समय में प्रत्येक देश अपनी विशिष्ट भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अवस्थाओं के अनुसार एक सन्तुलित प्रादेशिक विकास के लिए प्रयत्नशील है। भारत जैसे देशों में विकास की योजनाऐं प्रचलित हैं, परन्तु सफल नीति निर्धारण का अभाव होने से असन्तुलित प्रादेशिक विकास हो रहा है। समग्र ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है कि वहां उपलब्ध सभी प्राकृतिक संसाधनों का सन्तुलित एवं समुचित उपयोग हो सके। इसलिए स्थानिक कार्यात्मक नियोजन द्वारा सामाजिक आर्थिक सुविधाओं का विभिन्न क्षेत्रों में उचित वितरण हो ताकि सर्वांगीण विकास हो सके।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधकार्य का मुख्य उद्देश्य बून्दी जिले में सूक्ष्म स्तर पर सन्तुलित विकास है अर्थात् विभिन्न सेवाओं एवं सुविधाओं के विकास के लिए

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन करना है।

जिले के समग्र विकास हेतु निम्न उद्देश्य रखे गये हैं :–

1. प्रत्येक केन्द्रीय कार्य की महत्ता की जांच करना।
2. संसाधनों के आधार पर जिले के अधिवासों का स्तरीकरण करना
3. उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का क्षेत्रीय विकास की योजना प्रस्तुत करना।
4. केन्द्रीय कार्यों की उपलब्धता के आधार पर नवीन केन्द्रीय स्थलों को विकसित करने का सुझाव देना।
5. जिले की सामाजिक–आर्थिक संरचना के समग्र विकास के लिए नियोजन करना।

विधी तंत्र

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, पेयजल एवं बाजार सम्बन्धी आंकड़ों से सांख्यिकीय विधियों द्वारा केन्द्रीयता एवं पदानुक्रम ज्ञात किया गया है।

साहित्यावलोकन

भट्ट (1972) ने अपने शोध ग्रन्थ ''रीजनल प्लानिंग इन इण्डिया'' में हरियाणा के करनाल जिले के नियोजन में 23 सामाजिक चरमूल्य लेकर ग्रामीण अधिवासों का पदानुक्रम निर्धारित किया। यादव, संदीप (2001) ने अपने शोध ग्रन्थ ''स्पेशियो फंक्शनल प्लानिंग इन राजस्थानः एक माइक्रो एनालिटीकल स्टडी ऑफ ब्यावर तहसील'' में वृद्धि केन्द्रों एवं सेवा केन्द्रों के माध्यम से तहसील के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 30 चर मूल्य लेकर नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की। सिंह, धर्मेन्द्र (2007) ने ''अलीगढ़ नगर में स्वास्थ्य सुविधा'' शोध ग्रन्थ में अलीगढ़ नगर की स्वास्थ्य सुविधाओं का अध्ययन किया, परन्तु स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों की गुणवत्ता का उल्लेख नहीं किया गया। राणावत, डी.एस. (2010) ने ''एकीकृत ग्रामीण विकास योजना'' (झालरापाटन तहसील का अध्ययन) में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के क्षेत्रीय विकास के लिए विभिन्न आयामों का विवेचन किया, परन्तु विकास के लिए कौशल एवं क्षमताओं की विवेचना नहीं की गयी। नागर, रवि कुमार (2018) ने ''समग्र क्षेत्र विकास नियोजन'' मांगरोल तहसील का भौगोलिक अध्ययन में विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा केन्द्रों का निर्धारण करते हुए स्थानिक सम्बद्धता एवं रिक्तता के क्षेत्रों का विवेचन करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए कार्यात्मक पदानुक्रम के अनुरूप विकास के प्रस्ताव दिये हैं। मंगल निकिता (2018) ने ''एकीकृत ग्रामीण विकास योजना देवली तहसील का अध्ययन'' में ग्रामीण विकास में भौगोलिक तत्वों की भूमिका, उपलब्ध संसाधनों के विकास में प्रभाव, कृषि आधारित उद्योगों के विशेष संदर्भ मे उपलब्ध आर्थिक अवसरों की महत्ता का अध्ययन किया है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-10* June- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

Key Map of Bundi District

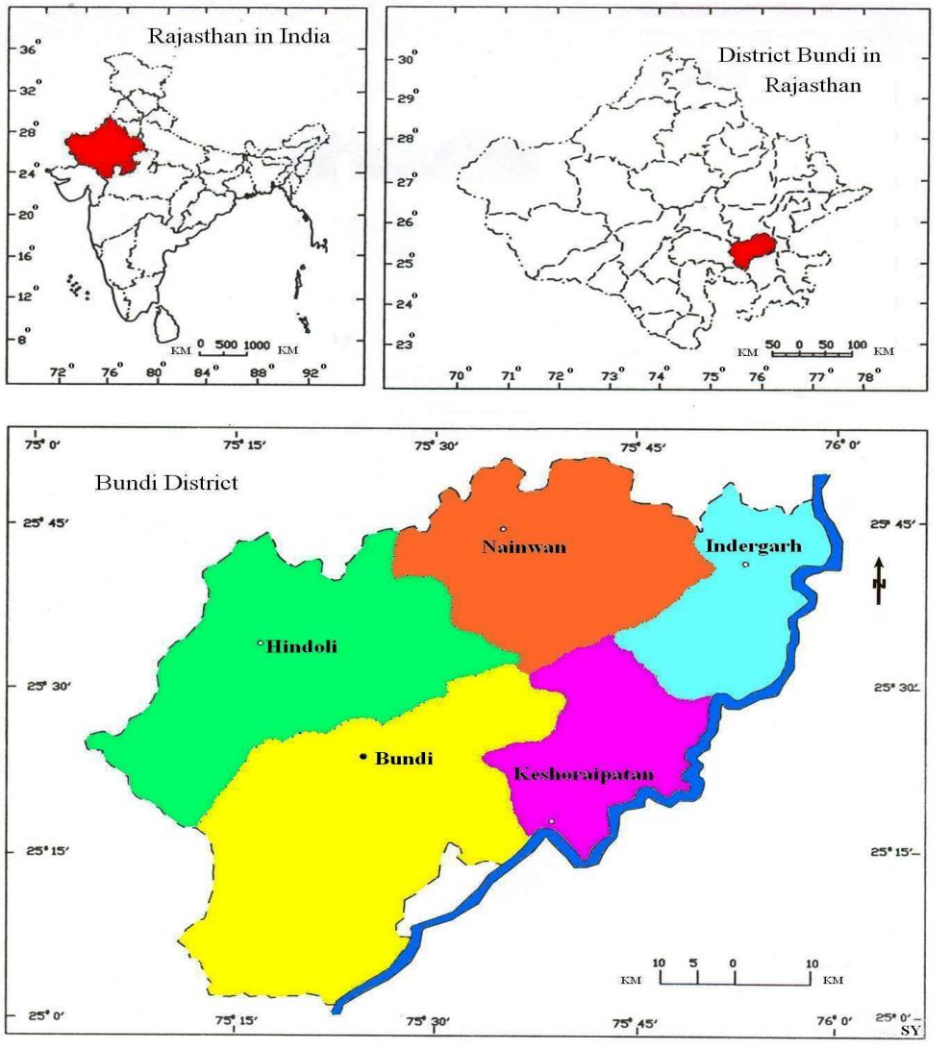

अध्ययन क्षेत्र

बून्दी जिला राजस्थान के दक्षिण–पूर्वी भाग में हाड़ौती के पठार में स्थित है। विषम कोणीय चतुर्भुज आकार में फैले इस जिले का विस्तार $24^0 59'$ उत्तरी अंक्षाश से $25^0 53'$ उत्तरी अंक्षाशों तक तथा $75^0 19' 30''$ पूर्वी देशान्तर से $76^0 19' 30''$ पूर्वी देशान्तरों के मध्य है। पूर्व से पश्चिम 111 किमी की लम्बाई एवं उत्तर से दक्षिण 105 किमी की चौड़ाई में फैले हुए सम्पूर्ण जिले का क्षेत्रफल 5850 वर्ग किमी है तथा 2011 में जनसंख्या 110906 है। जिले में 5 तहसीलें, 182 ग्राम पंचायतें, 892 अधिवास एवं 6 नगरीय केन्द्र हैं।

केन्द्रीय कार्य की संकल्पना

किसी भी प्रदेश के अधिवासों में ऐसी स्थानिक अवस्थिति जो अपने चारों ओर के समीपवर्ती क्षेत्रों को वस्तुऐं एवं सेवाऐं प्रदान करता है, उसे सेवा केन्द्रों के रूप में माना जाता है। वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियां सेवा केन्द्रों के व्यापक कार्य होते हैं और जनसंख्या व उसकी संरचना उनके सापेक्षिक महत्व को इंगित करते हैं। तालिका 1 में कार्यिक भार प्रो0एल.एस.भट्ट के निम्न सूत्र से ज्ञात किया गया है।

$$Wi = \frac{N}{Fi}$$

यहॉ Wi = उप कार्य का भार

Fi = कुल अधिवास जहां वह सेवा है

N = कुल अधिवास

अध्ययन क्षेत्र के गहन निरीक्षण हेतु उन सेवाओं को चुना है जो यहां के निवासियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर को निर्धारित करते हैं जैसे– शिक्षा, चिकित्सा, बाजार, पेयजल, खाद्य आपूर्ति, परिवहन, बैकिंग, डाक एवं अन्य सेवायें।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-10* June- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

तालिका 1
जिला बून्दी : सेवाओं का कार्यिक भार

क्र.सं.	सेवा का नाम	कुल अधिवास जहां सेवा है	कार्यिक भार
1.	प्राथमिक विद्यालय	187	1.01
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	177	1.06
3.	माध्यमिक–उच्च माध्यमिक विद्यालय	143	1.31
4.	महाविद्यालय	4	47
5.	स्वास्थ्य केन्द्र	21	8.95
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	44	4.27
7.	प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र	154	1.22
8.	परिवार कल्याण सेवा	24	7.83
9.	अस्पताल	7	26.86
10	पेयजल आपूर्ति	131	1.43
11	सार्वजनिक वितरण केन्द्र	186	1.01
12	वाणिज्यक बैंक	70	2.69
13	सहकारी बैंक	74	2.54
14	सहकारी समिति	104	1.81
15	विश्राम गृह	24	7.83
16	पुस्तकालय	30	6.27
17	खेल का मैदान	187	1.01
18	डाकघर व उप डाकघर	168	1.12
19	तहसील मुख्यालय	5	37.6
20	जिला मुख्यालय	1	188
21	उर्वरक एवं बीज केन्द्र	76	2.47
22	पशु चिकित्सा केन्द्र	46	4.09
23	बस परिवहन सेवा	102	1.84
24	नियमित बाजार	90	2.09
25	हाट बाजार	36	5.22
26	थोक बाजार	32	5.87
27	सिनेमा	14	13.43
28	रेल परिवहन सेवा	20	9.40
29	ईंधन आपूर्ति केन्द्र	35	5.37
30	घरेलू उद्योग	127	1.48
31	कोरियर सेवा	13	14.46
32	कम्यूनिटी सेन्टर	183	1.03
33	ATM सुविधा	32	5.87

उक्त सेवाओं के वितरण में निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये–

1. उच्च सेवायें जैसे माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, बैंक, मनोरंजन के साधन, बाजार आदि उन अधिवासों में मिलती है जिनकी जनसंख्या 6000 से अधिक है। यहां यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि यहां अधिवासों के आकार के आधार पर सेवाओं के वितरण में एक बहुत बड़ी रिक्तता है।
2. 4000 से कम जनसंख्या वाले अधिवासों में बहुत कम सेवायें हैं। इनमें उच्च प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, खाद्य आपूर्ति, डाकघर जैसी निम्न सेवायें मिलती हैं।
3. जो अधिवास 4000 से 6000 की जनसंख्या वाले हैं वहां निम्न सेवाओं के अलावा उप स्वास्थ्य केन्द्र, नियमित बाजार, बैंक, बस सेवा, उर्वरक केन्द्र आदि सेवायें उपलब्ध हैं।

सेवाओं का पदानुक्रम

अध्ययन क्षेत्र की प्रत्येक इकाई (पंचायत) में सेवाओं की सुविधायुक्त एवं सुविधारहित स्थिति को सारणीबद्ध करके प्रो0एल.एस.भट्ट की कार्यभार विधि का प्रयोग करते हुए विभिन्न सेवाओं का भार निर्धारित करते हुए सूचकांक ज्ञात किये हैं :–

$$Cj = \sum_{i=1}^{k} WiXij$$

Cj = अधिवासों के लिए संयुक्त कार्यभारी
Wi = सेवा का भार
Xij = अधिवास में i सेवा सेवा का भार
k = किसी सेवा की उपसेवा का योग

अध्ययन क्षेत्र में जिस सेवा की अधिक अधिवासों में उपस्थिति है, उसे कम भार तथा कम अधिवासों में सेवा कम होने पर अधिक भार आया है। यह निष्कर्ष केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त के अनुरूप है। तालिका 1 के अनुसार जिले में सेवाओं के पदानुक्रम निर्धारण के लिए 31 प्रकार की सेवाओं में से खाद्य आपूर्ति, प्राथमिक विद्यालय एवं खेल के मैदान का कार्यिक भार सबसे कम 1.01 तथा प्रशासनिक सेवा में जिला मुख्यालय का कार्यभार सर्वाधिक 188 है। अध्ययन क्षेत्र में एकमात्र जिला मुख्यालय होने से कार्यिक भार सर्वाधिक है।

सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम

कार्यात्मक नियोजन में पदानुक्रम का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। पदानुक्रम से आशय अधिवासों को उनके आकार एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों तथा उपलब्ध सेवाओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करना है। किसी भी अधिवास में नयी सेवा की सुविधा प्रारम्भ करने के लिए पदानुक्रम प्रमुख आधार माना जाता है। पदानुक्रम के आधार पर ही सेवा उपलब्ध करवायी जाती है।

जिले की 182 ग्राम पंचायतों एवं 6 नगर पालिका क्षेत्रों में सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम हेतु कार्यों एवं सेवाओं के आधार पर अलग–अलग केन्द्रियता सूचकांक ज्ञात करके प्रत्येक इकाई को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके द्वि–लघुगणकीय ग्राफ पर आलेखित किया गया। ग्राफ पर चार विच्छेदित बिन्दुओं के आधार पर सेवा क्षेत्र के सेवा केन्द्रों को पाँच पदानुक्रमीय वर्गों में विभक्त किया गया।

कार्यात्मक केन्द्रीयता एवं जनसंख्या आकार

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या आकार एवं केन्द्रीयता सूचकांक में कार्ल पियर्सन विधि द्वारा उच्च घनात्मक सहसम्बन्ध (0.94) प्राप्त हुआ है। तालिका 2 से स्पष्ट है कि जैसे–जैसे पदानुक्रम स्तर में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे अधिवासों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक 173 अधिवास पदानुक्रम के पांचवे स्तर में स्थित है अर्थात जिले की 92.02 प्रतिशत अधिवास पंचम स्तर में आते हैं। अध्ययन क्षेत्र के 6 नगरीय अधिवासों में एक बून्दी प्रथम स्तर में स्थित है जिसका केन्द्रीयता सूचकांक 818.02 है। बून्दी नगर जिला मुख्यालय होने के कारण सेवाओं की उपलब्धता का स्तर ऊँचा है।

तालिका–2

पदानुक्रम स्तर	केन्द्रीयता सूचकांक	अधिवासों की सं0	कुल का प्रतिशत
I	500 से अधिक	1	0.53
II	250 से 500	4	2.13
III	150 से 250	2	1.06
IV	75 से 150	9	4.79
V	75 से कम	172	91.49
योग		188	100

पदानुक्रमीय तंत्र का स्थानिक वितरण

प्रथम स्तर के अधिवास

तालिका–2 से स्पष्ट है कि पदानुक्रम के प्रथम स्तर में बून्दी नगर है जिसका केन्द्रियता सूचकांक 818.02 है जहां 14 प्रकार की सेवायें उपलब्ध हैं। नगर मध्य में स्थित होने के कारण सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के अधिवासों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 चारलेन द्वारा प्रादेशिक राजधानी जयपुर से सीधा जुड़ा हुआ है।

द्वितीय स्तर के अधिवास

अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों के द्वितीय पदानुक्रम स्तर में चार अधिवास लाखेरी, नैनवां, केशोराय पाटन एवं काप्रेन निर्धारित हुये हैं जो गनरीय अधिवास हैं। द्वितीय स्तर में सभी उच्च सेवाऐं जैसे महाविद्यालय, विश्रामगृह, चिकित्सालय, पुस्तकालय आदि उपलब्ध हैं। नैनवां की तहसील मुख्यालय एवं बड़ा अधिवास का होना, लाखेरी सीमेन्ट उद्योग का केन्द्र तथा लाखेरी, केशोराय पाटन व काप्रेन दिल्ली–मुम्बई बड़ी रेल लाईन पर स्थित है तथा आस–पास के तृतीय एवं चतुर्थ स्तर के अधिवासों को सेवायें प्रदान करते हैं।

तृतीय स्तर के अधिवास

पदानुक्रम के तृतीय स्तर में जिले के दो अधिवास हिण्डोली एवं इन्द्रगढ़ स्थित हैं। हिण्डोली तहसील मुख्यालय है जहां कॉलेज एवं रेल सेवा के अलावा सभी 12 सेवाऐं उपलब्ध हैं। इसका केन्द्रियता सूचकांक 174.4 है तथा इन्द्रगढ़ का 186 है। इन्द्रगढ़ दिल्ली मुम्बई रेल लाईन से जुड़ा हुआ है तथा महाविद्यालय एवं सिनेमा को छोड़कर सभी सेवाऐं उपलब्ध हैं। इन दोनों अधिवासों के आस–पास के चतुर्थ एवं पंचम स्तर के अधिवास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं से करते हैं।

चतुर्थ स्तर के अधिवास

अध्ययन क्षेत्र के अधिवासों के पदानुक्रम के चतुर्थ स्तर में 9 अधिवास डाबी (131.58), देई (120), धनेश्वर (107.27), गोठड़ा (117.51), करवर (107.25), बड़ानयागाँव (99.6), माटून्दा (92.04), अकतासा (83.63) एवं अलोद (77.65) सम्मिलित हुए हैं। ये जिले के बड़े अधिवास हैं जो सभी तहसीलों में वितरित हैं तथा 9 प्रकार की सेवाऐं उपलब्ध हैं। चतुर्थ स्तर के ये सभी अधिवास

अपने निकटवर्ती पंचम स्तर के सभी अधिवासों को सेवयें प्रदान करते हैं।

पंचम स्तर के अधिवास

जिले के 172 अधिवास पदानुक्रम के पंचम स्तर के अन्तर्गत सम्मिलित हुए हैं जहां शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, खाद्य आपूर्ति खाद एवं उर्वरक एवं पेयजल की सेवायें उपलब्ध हैं। इन अधिवासों का केन्द्रियता सूचकांक 75 से कम है तथा उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए अपने से उच्च स्तर के अधिवासों पर निर्भर रहना पड़ता है।

निष्कर्ष

किसी भी प्रदेश में अधिवास पदानुक्रमों का अस्तित्व और कार्यात्मक केन्द्रों का वितरण काफी हद तक भौतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों पर निर्भर करता है। अध्ययन क्षेत्र में भौतिक एवं सामाजिक–आर्थिक बाध्यताओं से आर्थिक विकास को बाधित किया है। अध्ययन क्षेत्र का लगभग आधा भाग काफी पिछड़ा हुआ है। केवल आत्मनिर्भर कृषि एवं पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय है। शेष क्षेत्र में कृषि काफी उन्नत है और यहां विकास के लिए कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, उर्वरक एवं बीज आदि सेवाओं का विस्तार अपेक्षित है और यह तभी संभव है तब यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो। अन्त में जिले का सुनियोजित विकास तभी संभव है जब ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों में पर्याप्त संरचनात्मक सुविधाओं का नियोजित ढंग से विकास हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *Bhatt, L.S. 'Micro Level Planning: A case study of Karnal Area, India', 1976.*
2. *Budhraja, J.C. "Micro Level Development Planning" (Rural Growth Centre Strategy) common wealth publishers, Delhi, 1987.*
3. *Berry, BJL & W.H Garrison – The functional Bases of Central Place Hierarchy, Economic Geography, 34, 1953, PP 145-154.*
4. *District Census Handbook, Bundi- 2011.*
5. *Mandal, R.B., Sinha VNP, Recent trends & concepts in Geography Vol.III Concept Publishing company, New Delhi.*
6. *Negi, D.S. "Functional Analysis and Hierarchy of service centres in District Bijnor, an unpublished Ph.D. Thesis Meerut, 1974.*